

समाचार सार

15 लाख के गांजा के साथ दबोचे गए 7 तस्क़र



बलीदा बाजार। आपरेशन निक्षय के तहत सिमगा पुलिस ने महासमुंद और बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर ओडिशा से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश गांजा ले जा रहे 7 शातिर तस्क़रों को रंग हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्क़रों में एक आरोपियों में से एक स्थानीय स्तर पर पत्रकार के सहायक के रूप में जुड़ा हुआ था, और चेकिंग के दौरान इसी पहचान का सहारा लेकर बचने का प्रयास करता था। जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर को सिमगा पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि ओडिशा की ओर से एक सफेद स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में अवैध गांजा भरकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। गिराह की कार्यप्रणाली बेहद शातिर थी, तस्क़र पुलिस की गतिविधियों को रोकने के लिए स्विफ्ट कार के आगे-आगे एक बलेनी कार को 'पायलट वाहन' के रूप में दौड़ा रहे थे।

एनएसई चीफ ने साइबर हमलों पर किया सतर्क

मुंबई। भारतीय पूंजी बाजार के अभूतपूर्व विस्तार के बीच वित्तीय बुनियादी ढांचे पर तकनीकी खतरों का जोखिम भी तेजी से बढ़ गया है। मुंबई में आयोजित 16वें एनएमआई अंतरराष्ट्रीय कैपिटल मार्केट कन्वेंशन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशीष कुमार चौहान ने इस बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि एआई-संचालित साइबर जोखिम और क्राइम कंप्यूटिंग की चुनौतियां बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने को दिशा में कठिन परीक्षा कर रहे हैं।

बादाम और पिस्ता की ऊंची कीमतों के बावजूद बिक्री बढ़ने की उम्मीद

मुंबई। वैश्विक स्तर पर बढ़े हुए तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष की वजह से ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से बादाम तथ अन्य ड्राई फ्रूट्स (सूखे मेवे) की आपूर्ति प्रभावित हुई। जिसकी वजह से पिस्ता, बादाम अखरोट की कीमतों पिछले साल की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ी हुई हैं। बावजूद इसके धनतेरस, दिवाली और भाईदूज पर कारोबारियों को बिक्री अच्छी होने की उम्मीद है। मुंबई मेवा मसाला मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश गणगना ने अमर उजाला डॉटकॉम के साथ बातचीत में बताया कि, पिछले साल की तुलना में बादाम, पिस्ता, अखरोट के कीमते 20 से 30 प्रतिशत बढ़ी हैं, लेकिन बाजार में मांग बनी हुई है। उपहार के रूप में देने के लिए हमें अच्छे आईडर मिल रहे हैं, लेकिन यह कह सकते हैं, उनकी मात्रा कम हो गई है।

सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो की तैयारियों की कलेक्टर सिंह ने की समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ रा्न्त्योत्सव 2026 के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित सैंध लेक क्षेत्र में आयोजित होने वाले सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला प्रशासन, नगर निगम तथा विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एयर शो के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए की जा रही

तैयारियों को विस्तृत समीक्षा की गई तथा सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और दर्शकों की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने,

यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने तथा दर्शकों एवं अतिथियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, परिवहन व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन की

तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही ड्रॉप जॉन की लेबलिंग, आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं आवागमन की व्यवस्था तथा किसी और कार्यक्रम से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम समय पर सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई। एयर शो के सफल

गढफुलझर में 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वमंगल भवन का किया लोकार्पण

सुशासन और पारदर्शिता के साथ हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

गढफुलझर में बाबा विशासहे कुल कोलता समाज के वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन में शामिल हुए

मंदिर परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से भव्य डोम निर्माण की घोषणा की

मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण सहित क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्य

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत गढफुलझर में बाबा विशासहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वमंगल भवन का लोकार्पण किया।

उन्होंने समाज की मांग पर मंदिर परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से भव्य डोम निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2024 में गढफुलझर के विकास के लिए किए



मोदी की गारंटी के संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही राज्य सरकार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार जनकल्याण से जुड़े संकल्पों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उल्लेख करते हुए कहा कि आवास से वंचित गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1,600 आवासों का निर्माण हो रहा है।

गए वादे अब धरातल पर साकार हो रहे हैं। सर्वमंगल भवन का निर्माण पूरा होने से सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 48 लाख रुपये की लागत से मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में लगभग पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी प्रगति पर है, जिस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से गढफुलझर और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गढफुलझर में विकास का बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को और गति दी जाएगी।

सुशासन और पारदर्शिता के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग

साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।

पर्यटन और सिंचाई परियोजनाओं से खुलेंगे विकास एवं रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था, पुरातात्विक विरासत और समृद्ध संस्कृति से परिपूर्ण है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के साथ होमस्टे जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने सिरपुर बैराज तथा शिकासेर-कोडर लिंक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों की समृद्धि और कृषि उत्पादन में वृद्धि का आधार बनेगा।

दवाएं सस्ती हों, ग्रामीणों तक पहुंचे इलाज, नकली दवाओं पर लगे रोक : राज्यपाल डेका

एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि सस्ता इलाज, किफायती दवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना देश की प्रमुख चुनौतियां हैं। इनके समाधान के लिए चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा को केवल कारीबार नहीं, बल्कि समाजसेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने नकली दवाओं पर रोक लगाने, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक शोध करने और छत्तीसगढ़ की वनोपधियों के पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री डेका आज पॉइंट रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया (एपीटीआई) के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 को संबोधित कर रहे थे। अधिवेशन का विषय फार्मा शिखर आत्मनिर्भर भारत के लिए फार्मासिस्ट तैयार करने का संकल्प था। राज्यपाल ने कहा कि देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण आबादी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना अब भी चुनौती है। दवाओं



की कीमत आम आदमी को पहुंच में होनी चाहिए। चिकित्सकों को दवाएं लिखते समय मरीज की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और जहां संभव हो, कम कीमत वाली प्रभावी दवाओं के विकल्प अपनाने चाहिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सकों और फार्मासिस्टों को गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करना होगा। गर्भवती महिलाओं, माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर बैगा समुदाय के पास औषधीय पौधों और पारंपरिक उपचार पद्धतियों से जुड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परंपराओं में उपलब्ध जानकारी को आधुनिक शोध के माध्यम से जांच कर उनकी उपयोगिता का आकलन करना जरूरी है।

जॉर्डन में चर्च पर हमला

भारत ने की कड़ी निंदा, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दोहराया

नई दिल्ली (ए)। भारत ने शुक्रवार को जॉर्डन के करार में एक चर्च पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में सात लोगों की मौत हो गई। वहीं, 34 अन्य लोग घायल हो गए। विदेश मंत्रालय (एमए) ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें नई दिल्ली ने हमले को नृशंस और कारगरतापूर्ण बताया।



लोगों की दुखद मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। हम मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हैं। साथ ही, इस कारगरतापूर्ण हमले में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बयान में आगे कहा गया, इस मुश्किल घड़ी में भारत जॉर्डन की सरकार और वहां के मित्रवत लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। हम आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों के खिलाफ लड़ाई के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं।

एस जयशंकर ने क्या कहा ? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कल जॉर्डन के करार में एक चर्च पर हुए नृशंस हमले से मैं बेहद दुखी हूँ।

रेड नदी हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

सूरजपुर। जिले में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के स्थस्वतीपुर गांव निवासी रेड नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। मृतकों में पिता-पुत्र और उनके रिश्ते के दो नाबालिग भतीजे शामिल हैं। चारों मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले थे। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है, वहीं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतकों की पहचान विवेक कुमार सिंह (45 वर्ष), पिता विश्वनाथ सिंह, आंभजीत सिंह (20 वर्ष), पिता विवेक सिंह, गोपाल कृष्ण (करीब 13 वर्ष) और कृष्ण गोपाल (करीब 15 वर्ष), दोनों के पिता जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, कृष्ण गोपाल और गोपाल कृष्ण की मौसी सूरजपुर के चंदरपुर नवापारा में रहती हैं, जहां वह ब्यूटी पॉलर संचालित करती हैं। परिवार के लोग घूमने और अपनों के साथ समय बिताने के लिए सूरजपुर आए हुए थे। बताया जा रहा है कि जिस जगह यह दर्दनाक हादसा हुआ, वहां परिवार के लोग एक दिन पहले भी घूमने गए थे।



पुलिस ने सभी के शव किए बरामद, बिहार से आए थे घूमने

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस हमले के तार इंदौर से जुड़े, साजिश में शामिल सदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया

इंदौर/मुंबई (ए)। एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश के तार अब इंदौर से जुड़ गए हैं। मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग कर हत्या की कोशिश के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रांजल नामक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह हमले की प्लानिंग में शामिल था। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपी के इंदौर में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए प्रांजल को हिरासत में लिया। अब पुलिस उससे पुख्ताछ कर साजिश से जुड़ी जानकारीयां जुटाने का प्रयास कर रही है।



वहीं मुंबई डीसीपी राज तिलक रीशन ने शनिवार को बताया कि इस गिरफ्तारी के साथ ही केस में अब तक कुल 11

पुलिस हिरासत की मांग की थी। पुलिस ने रिमांड एप्लीकेशन में अदालत को बताया कि टाइगर श्रॉफ पर हमला भी आतंक फैलाने की उसी सोच-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका खुलासा सलमान खान पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी के मामलों में पुलिस चार्जशीट में पहले ही कर चुकी है। अदालत में दो गई रिमांड एप्लीकेशन के अनुसार, गिरफ्तार किए गए इन तीनों आरोपियों ने वारदात से पहले मुंबई में कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों के घरों की भी रेकी की थी। रिमांड एप्लीकेशन में यह भी खुलासा हुआ है कि इस हमले को अंजाम देने के बाद आरोपियों की योजना विदेश भागने की थी।

सड़क निर्माण के दौरान विस्फोट, चालक समेत 5 लोगों की मौत, दो वाहन क्षतिग्रस्त

जगदलपुर (ए)। आंध्रप्रदेश के अछूरी गाई। जानकारी के मुताबिक, सड़क निर्माण कीमतार राजू जिले में शनिवार सुबह भीषण विस्फोट होने से पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा अनंतगिरि मंडल के पिनाकोटा में सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुआ।

जानकारी के अनुसार, जिलेटिन की छड़ों से जुड़े विस्फोटक उपकरण में अचानक धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक चालक और चार मजदूरों की जान चली गई।



इसकी वजह से दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

शहर सीट पर हिंदू को उतार सकती है सपा अखिलेश और आजम के बीच भी हुई चर्चा, रणनीति बदलने की अटकलें

मुगदाबाद (ए)। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर हलचल तेज हो गई है। 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खां के बीच प्रदेश की जिन प्रमुख सीटों को लेकर चर्चा हुई उनमें मुगदाबाद शहर सीट भी शामिल है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि पार्टी करीब 20 साल बाद मुगदाबाद शहर सीट से किसी हिंदू

नई सीट पर लगातार दो बार मिली हार

वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद मुगदाबाद नगर सीट का मौजूदा स्वरूप बना। वर्ष 2012 में सपा ने मोहम्मद यूसुफ अंसारी को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने भाजपा के रितेश कुमार गुप्ता को 20,238 मतो से हराया। लेकिन वर्ष 2017 में यूसुफ अंसारी 3,193 मतो से चुनाव हार गए। वर्ष 2022 में मुकाबला और करीबी रहा। भाजपा के रितेश कुमार गुप्ता ने महज 782 मतो से जीत दर्ज की।



प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। रामपुर जेल में करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खां ने कोई सीट नहीं मांगी, बल्कि कुछ सुझाव दिए हैं।

हर घर जल उत्सव के साथ ग्रामीण सहभागिता और जल संरक्षण का लिया संकल्प

ग्राम कचोरा में जल जीवन मिशन से 24 परिवारों को मिला शुद्ध पेयजल, ग्रामीणों की भागीदारी से सुदृढ़ हो रही जलापूर्ति व्यवस्था

नारायणपुर/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन दूरस्थ अंचलों में जनजीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत महोरा के आश्रित ग्राम कचोरा में जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीणों को घर-घर नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। योजना के क्रियान्वयन से गांव के 24 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से राहत मिली है और उनके दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ी है।

क्लेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम कचोरा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रामीणों को जल संरक्षण, स्वच्छता और योजना के नियमित संचालन के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

पेयजल की समस्या से मिली राहत, घर-घर पहुंचा नल से जल -ग्राम कचोरा में कुल 24 परिवार निवासस्थ हैं। यहां के अधिकांश ग्रामीण कृषि आधारित आजीविका से जुड़े



हैं तथा पारंपरिक रूप से खेती-किसानी करते हैं। गांव की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित सुविधाओं के कारण पहले ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विशेषकर परिवारों की महिलाओं को पेयजल की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। ग्रामीणों की इस समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था विकसित की गई। योजना के तहत गांव में लगभग 2084 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई तथा 10,000 लीटर क्षमता वाली दो सोलर आधारित पानी की टंकियों का निर्माण किया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से गांव के सभी 24 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिली है तथा समय और श्रम की बचत भी हो रही है।



हर घर जल उत्सव के माध्यम से लिया जल संरक्षण का संकल्प -योजना के सफल क्रियान्वयन के उपरांत ग्राम कचोरा में ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्रामसभा का आयोजन कर हर घर जल उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से पेयजल व्यवस्था के प्रति अपनी सामुदायिक जिम्मेदारी निभाने और जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लिया। ग्रामीणों को बताया गया कि नल से जल की सुविधा उपलब्ध होने के बाद उसका नियमित एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना भी आवश्यक है। जल की बर्बादी रोकना, पेयजल स्रोतों को स्वच्छ रखना तथा जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव में सहयोग देना प्रत्येक ग्रामीण की जिम्मेदारी है।

जनभागीदारी से सुनिश्चित होगा योजना का बेहतर संचालन -ग्राम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से

संचालित करने के लिए पंप ऑपरेटर के रूप में श्री माया राम कोमरा तथा इलेक्ट्रीशियन के रूप में श्री सुनील कुमार सोरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पांच महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है।

योजना के संचालन, निगरानी और रखरखाव में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन भी किया गया है। यह व्यवस्था ग्रामीणों को अपनी पेयजल सुविधा के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय होने से पेयजल आपूर्ति की निगरानी, जल गुणवत्ता परीक्षण और आवश्यक रखरखाव में सहयोग मिलेगा। ग्राम कचोरा की यह सफलता दर्शाती है कि शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी मिलकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही सामुदायिक जिम्मेदारी, स्वच्छता और जल संरक्षण की भावना भी मजबूत हो रही है। घर-घर नल से जल की सुविधा अब ग्रामीण परिवारों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ सुरक्षित पेयजल और बेहतर ग्रामीण जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

समाज सेविका मीनल अंकित अग्रवाल को मिली प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी



आशा गोयल बनाई गई प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन में नारी शक्ति को मिली नई जिम्मेदारियां

सक्ति। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई द्वारा शक्ति की समाज सेविका एवं मारवाड़ी युवा मंच महिला जागृति शाखा की उज्ज्वान अध्यक्ष श्रीमती मीनल अंकित अग्रवाल को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तथा इसके साथ ही शक्ति की वरिष्ठ समाज सेविका

एवं पूर्व में विभिन्न सामाजिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुकी श्रीमती आशा गोयल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपरोक्त दोनों नियुक्ति पर शक्ति की महिला समिति की सदस्यों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा है कि इन दोनों महिला सदस्यों को मिली नई जिम्मेदारियों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन का संघटन मजबूत होगा तो वहीं श्रीमती मीनल अग्रवाल ने भी कहा है कि प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं पूरी सजगता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करूंगी।

अछोली में विजयदशमी पर्व पर धूमधाम से मनाया गया



डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम अछोली प्रतिवर्ष अनुरा इस वर्ष भी नया अछोली के स्कूल मैदान में श्री श्री कान्हा दशहरा उत्सव समिति के द्वारा 22 अक्टूबर दिन गुरुवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच नंद कुमार साहू, विशिष्ट अतिथि उत्सवसंचालक पुष्पाज

साहू, वरिष्ठ नागरिक पिरंगी राम पटेल, पूर्व सरपंच विजय पांडे (टेना महाराज)योधन दास साहू, के द्वारा सर्वप्रथम भगवान राम का पुष्प माला अर्पित कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर किया गया, तत्पश्चात कान्हागंगा की श्री राम भक्त मानस परिवार रामलीला, मनमोहन

रामलीला का आयोजन किया गया भारी संख्या में उपस्थित भीड़ ने खुब आनंद उछाया, वहीं अंत में जौरदार आतिशबाजियों के साथ रावण दहन किया गया कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समिति के सदस्यों ने उपस्थित जनसमुदाय एवं ग्राम वासियों का आभार व्यक्त किया है।

विकासखंड स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में बच्चों में दिखा उत्साह युवा संसद प्रतियोगिता में सत्ता पक्ष व विपक्ष की भूमिका में छाये बच्चे

आरंग। गुरुवार को विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा के निर्देशन में गांधी इंस्टीट्यूट स्कूल आरंग में विकासखंड स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विकासखंड के 8 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने बह-चक्रर भाग लिया।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ।इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा ने प्रेरित करते हुवे कहा कि भारत युवाओ का देश है और युवा संसद केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि हमारे जीवंत लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को गहराई से समझने की उत्कृष्ट कार्यशाला है।उन्होंने प्रतिभागियों से अपेक्षा की कि वे विचारशील,ऊर्जावान युवा बनकर सशक्त विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए।इस अवसर पर उनके साथ सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी लाखेश्वर रात्रे,नोडल प्राचार्य गण संध्या रानी बारीक,सरोजनी केरकेड्ड,प्राचार्य गांधी हरेश दास,संकुल समन्वयक



हरीश दीवान की भी सहभागिता रही।इस प्रतियोगिता में पीएम श्री अरुंधती,शास कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरंग,हायर सेकेंडरी राखी, गनोद,गुड्ड,सेजेस समोदा स्कूल की सहभागिता रही।विद्यार्थियों ने ध्यानकार्षण में सायबर सुरक्षा,परिवहन विकास,राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,नारी सशक्तिकरण,जल वायु प्रदूषण नियंत्रण, मोबाइल के बढ़ते दुष्प्रभाव,मेरे सपनों का भारत जैसे मुद्दों से संसद की कार्यवाही का निभीकता से प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का सफल

अग्रवाल,जबिता देव,मनहरण यादव की भूमिका सराहनीय रही साथ ही शिक्षक गण हरमन भवेल,सीएसी अभिषेक तिवारी, वर्षारानी पाटकर,रजत पांडे,हरिनारायण साहू,सर्येंद्र त्रिपाठी आदि सभी की उत्कृष्ट सहभागिता रही।पीएमश्री शासकीय अरुंधति देवी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का चयन जिला स्तर के लिए किया गया। प्रतियोगिता के दौरान छात्र-छात्राओं ने संसदीय प्रक्रिया के तहत प्रश्न रखते हुए अपने-अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, एसपी अंकित शर्मा को पुलिस मुख्यालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

विजयादशमी पर पुलिस लाइन में पूजा-अर्चना के बाद AK-47 से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, विभागीय कार्रवाई पर टिकी

राजनांदगांव। विजयादशमी पर्व के अवसर पर राजनांदगांव पुलिस लाइन स्थित रक्षित आरक्षी केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में चर्चा तेज हो गई है।

कार्यक्रम में पूजा-अर्चना के पश्चात पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा द्वारा,च-47 राइफल से हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। जानकारी के अनुसार, विजयादशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में पारंपरिक रूप से शस्त्र पूजन का



कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान एसपी अंकित शर्मा के फायरिंग करने का दृश्य कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में एसपी को साड़ी पहने हुए,च-47 से फायरिंग करते देखा जा रहा है। वीडियो वायरल होने

के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली तथा उसकी सार्वजनिक छवि को लेकर सवाल उठने लगे।मामले के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस

स्पष्टीकरण और विभागीय स्तर पर होने वाली आगे की कार्रवाई को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले में राजनांदगांव रेंज के आईजी अजय कुमार यादव का बयान भी सामने आया है। हालांकि, प्रकरण में अंतिम स्थिति एसपी के जवाब और संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगी। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा के बीच सामने आए इस घटनाक्रम ने पुलिस विभाग को लेकर सार्वजनिक चर्चा को बढ़ा दिया है। फिहाल, कारण बताओ नोटिस के बाद मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मामले को अधिक संतुलित बनाइए

दादा पर नाती ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, सिरीखुर्द गांव की घटना, परिजनों ने आरोपी पर पहले भी हमले करने का लगाया आरोप

फिंशेर। थाना क्षेत्र के ग्राम सिरीखुर्द में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाती पर अपने ही बुजुर्ग दादा के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ओमकार सोनी को खून से लथपथ हालत में फिंशेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बुजुर्ग जिंदगी और पौर के बीच संघर्ष कर रहे हैं। घटना के बाद से परिवार में दहशत का माहौल है। परिजनों के मुताबिक, नवीन सोनी ने अपने दादा ओमकार सोनी के साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हालांकि, मारपीट के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फिंशेर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

पहले भी हमला करने का आरोप-परिजनों का आरोप है कि नवीन सोनी इससे पहले भी परिवार के सदस्यों पर कई बार जानलेवा हमला



कर चुका है और जेल भी जा चुका है। उनके मुताबिक, जेल से बाहर आने के बाद उसने एक बार फिर विवाद और मारपीट शुरू कर दी।आरोपी के चाचा भीमलाल सोनी ने बताया कि 31 मई 2026 को नवीन सोनी मुर्गी काटने वाले हथियार के साथ घर में घुसा था और परिवार के सदस्यों पर हमला करने की कोशिश की थी। उनका आरोप है कि उस समय पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई

नहीं की गई, जिसके चलते आरोपी के हौसले बढ़ गए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। परिवार में दहशत, कड़ी कार्रवाई की मांग-बुजुर्ग दादा के साथ हुई ताजा घटना ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया है। परिजनों का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद अब बुजुर्ग पर हुए हमले से परिवार को सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिहाल, घायल ओमकार सोनी की गंभीर हालत को लेकर परिजन चिंतित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब यह देखना होगा कि जांच में घटना के पीछे क्या कारण सामने आते हैं और पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।

श्रीमद्भगवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ !

मक्खन में छिपे हुए घी को निकालने के लिए मंथन जरूरी, वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्ममंथन जरूरी : कथा व्यास सविता गोस्वामी

चांपा। नगर के हृदय स्थल पर स्थित द मॉडर्न विलेज , चांपा में बांके बिहारी कृष्ण मुरारी जगत पालनकर्ता राधा रमण भगवान की असीम कृपा से सर्व जन कल्याण के प्रयोजनार्थ डॉक्टर श्रीमति शरद बिरथरे एवं डॉ विश्वनाथ बिरथरे के वैवाहिक जीवन के 50 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में संगीतमय श्रीमद्भगवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास श्रीमति सविता गोस्वामी दीदीजी ने भक्तों को जीवन का सार समझाते हुए बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रथम दिवस दिया। कथा व्यास सविता गोस्वामी जी ने कहा कि मक्खन में छिपे हुए घी को निकालने के लिए मंथन किया जाता है , उसी प्रकार सर्वत्र व्यास ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्ममंथन करना पड़ता है । इस अवसर पर आयोजित कथा यात्रा में डॉ सौरभ बिरथरे, डॉ पवनवी बिरथरे, डॉ स्वप्ति दुबे, डॉ विशाल दुबे, पूर्व न्यायध्यक्ष



राजेश अग्रवाल, प्रिंट मीडिया के शशिभूषण सोनी, डॉ रविन्द्र द्विवेदी, डॉ शिलाप हर्ष, डॉ धनंजय हर्ष, डॉ स्वर्णलता बिरथरे, संभुदयाल द्विवेदी, चित्रलेखा द्विवेदी, श्रीमति निर्मला श्रीमति शकुन द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त कथा का रसपान किए।स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद बिरथरे के जन्मोत्सव पर आयोजित श्रीमद्भगवत कथा में

सविता गोस्वामी ने विस्तार से समझाया कि जैसे दूध में घी सर्वत्र व्यास है लेकिन दिखता नहींह, उसे पाने के लिए दूध से दही , दही से मक्खन और मक्खन के मंथन के बाद घी प्राप्त होता है , ठीक उसी प्रकार ईश्वर कण-कण में व्यास है लेकिन उसे पाने के लिए मन का मंथन, आत्मा का चिंतन और भक्ति का ताप जरूरी है ।



श्रीमद्भगवत कथा महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ -वरिष्ठ चिकित्सक दर्पित डॉ श्रीमति शरद -विश्वनाथ बिरथरे परिवार के द्वारा संगीतमय श्रीमद्भगवत कथा से पूर्व तपस्वी बाबा के तपस्वली दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, डोगाघाट स्थित हसदेव नदी के तट से वृंदावन से प्रशिथित सुप्रसिद्ध कथा वाचिका श्रीमति सविता गोस्वामी दीदीजी की

कथा का शुभारंभ कलशयात्रा निकाल कर हुआ । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होने वाले श्रीमद्भगवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है । गुरुवार को 12 बजे से कलशयात्रा नगर निगमंत्रण देते हुए गाजे-बाजे के साथ द मॉडर्न विलेज पहुंची । इसमें मुख्य यजनमान डॉ श्रीमति शरद - डॉ

विश्वनाथ बिरथरे और अन्य श्रद्धालु भक्त सिर पर कलश धारण कर निकले । हसदेव नदी में प्रवाहित शुद्ध जल को कलश में भरने के बाद श्रीमद्भगवत कथा स्थल तक शोभायात्रा के रूप में पहुंची और फिर देव स्थापना के साथ सायंकाल 5:00 बजे कथा का शुभारंभ हुआ । पहले दिन वेदी पूजन,भागवत

कथा महातय , मंगलाचरण के साथ आरंभ हुआ । कीर्तन-भजन मंडली, महिलाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ी आभूषणों से सुसज्जित नृत्य और एक ही गुलाबी कलर में सजी-धजी महिलाएं ने शहर का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय कर दिया । व्यासपीठ पर विराजित परम पूजनीय श्रीमती सविता गोस्वामी जी की बिरथरे परिवार ने आत्मीय

स्वागत किया और उसके बाद मंगलाचरण के साथ शुक्रदेव जी की कथा का श्रीगणेश की । कलश यात्रा के संबंध में दीदीजी ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश पूजन किया जाता है । कलश में 133 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है । संगीतमय श्रीमद्भगवत कथा में उन्होंने भागवत कथा महातय का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में भागवत कथा ही वह मंथन है जो जीव के पापों को धोकर उसे ईश्वर से जोड़ती है । भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं , मोर-मुकुट वाले बांकेबिहारी के भजनों पर श्रोता देर रात्रि तक झुमते रहे ?इस पावन कथा ज्ञान यज्ञ में सुनील कुमार गोस्वामी, श्रीमति सोमा गोस्वामी, श्रीमति मंजू अग्रवाल, गीता सोनी, राजेश सोनी अर्जुन लाल सहित बड़ी संख्या में नगर के धर्मप्रेमी बंधु,भाएण-बहनें शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रही है ।

नगरीय निकाय निर्वाचन-2026 : निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन, राजनैतिक दलों को दी गई जानकारी

15 साल से बंद रास्ता होगा चालू

दर्जनभर से ज्यादा जारी नोटिस का नहीं हुआ असर, निगम ने हटाया अतिक्रमण

दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय निकाय निर्वाचन-2026 अंतर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को निकायों में किया गया है, जहां आगामी निर्वाचन होना है। इसके साथ ही दावे तथा आपत्ति प्राप्त करने के कार्य शुरू है। दावे आपत्ति 30 अक्टूबर के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निपटारा 03 नवम्बर 2026 तक किया जाएगा। दावे आपत्ति निष्करण के पश्चात् निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।

बैठक में नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2026 हेतु नियुक्त रजिस्ट्रीकरण/सहायक



/अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जानकारी दी गई। नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली एवं नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा तथा नगर पालिका परिषद जामूल अंतर्गत 170 वार्डों में 744 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। उक्त नगरीय निकायों में 507704 मतदाता हैं। राजनीतिक दलों को प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर की तिथि में मतदाताओं की संख्या और एसआईआर 21 फरवरी 2026 के

अनुसार मतदाताओं की संख्या तथा 01 अक्टूबर 2026 की तिथि में पूरक मतदाताओं की संख्या से भी अवगत कराया गया। विशेष पुनरीक्षण एसआईआर पश्चात् 21 फरवरी 2026 की स्थिति में नगरीय निकाय में मतदाताओं की संख्या भी जानकारी दी गई। इसी प्रकार प्रपत्र प्रारूप क, प्रारूप-ग-1, प्रारूप-ख एवं प्रारूप ग के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बैठक में

राजनीतिक दलों से भी सुझाव लिये गये तथा उनके शंकाओं का समाधान किया गया। बैठक समाप्ति पश्चात राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली प्रारंभिक प्रकाशन की कार्र्याय प्रदान की गई। बैठक में एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सिल्ली थामस, सभी एसडीएम एवं राजनीतिक दलों के जिला पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

रिसाली। वार्ड 13 स्थित मुख्य उई मार्ग पर पिछले 15 वर्षों से अवैध रूप से दुकान बनाकर व्यवसाय करने वाले को नगर पालिक निगम रिसाली ने खदेड़ दिया। शुक्रवार को निगम के राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंच कर बेदखली अभियान चलाया। अभियान के दौरान शुरूआत में विरोध का सामना अवश्य करना पड़ा। बाद में नेवई पुलिस की मध्यस्थता में तीन दुकानों को खाली कराने के बाद निगम के अधिकारियों ने दुकान को ढहा दिया। इस कार्यवाही से 15 साल से बंद आम रास्ता अब शुरू होगा।

इस कार्यवाही से पहले निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने एक साल पूर्व अतिक्रमण कर व्यापार करने वाले व्यापारियों को स्वतः दुकान हटाने निर्देश दिए थे। कई बार कार्यालय बुलाकर व्यापारियों को समझाश्री भी दी। इसके बाद भी चिकन कार्नर, सेलुन संचालक व इलेक्ट्रिक दुकान के संचालक हठधर्मिता पर अड़े रहे। आयुक्त के निर्देश पर राजस्व विभाग प्रभारी



धर्मेन्द्र मिश्रा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले दुकान से सामान बाहर निकालने मौका दिया। इसके बाद तीनों दुकान को हटया। दर्जनभर से ज्यादा नोटिस-वार्ड 13 टंकी मरोदा के पार्षद विधि यादव व नागरिकों ने पिछले दो वर्षों से अवरूद्ध मार्ग को शुरू कराने आयुक्त के समक्ष ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद से निगम प्रशासन अवरूद्ध मार्ग को शुरू कराने की सीधे शुरू की थी। लगभग दर्जनभर से ज्यादा नोटिस भी व्यापारियों को

दिया गया था। इसके बाद भी व्यापारी बेधड़क दुकान संचालित कर रहे थे। जल्द बनेगा सीसी रोड- मैत्री गार्डन चौक से सीधे वार्ड 13 जाने नहर किनारे से आम रास्ता बना हुआ है। निगम इस मार्ग पर सीमेंटीकरण कार्य कराया है। अतिक्रमण की वजह से मार्ग अवरूद्ध था और लगभग 50 मीटर सीमेंटीकरण कार्य पूर्ण करना बचा था। अतिक्रमण हटने से क्षेत्र के नागरिकों को कम दूरी तय कर वे सीधे मैत्री गार्डन चौक पहुंच सकते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र के 'मिशन लक्ष्मी' के तहत नदिनी माइंस में स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर संपन्न

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र, सेक्टर-9 द्वारा नदिनी माइंस अस्पताल में 'मिशन लक्ष्मी' के तहत एक दिवसीय स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्राओं, संविदा महिला कर्मचारियों, शिक्षकों और स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण, कैंसर की रोकथाम, स्वच्छता और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था।

महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से संचालित 'मिशन लक्ष्मी' के तहत जेएलएनएचआरसी की चिकित्सा टीम एवं बीएसपी के सीएसआर

विभाग द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। नदिनी माइंस में आयोजित शिविर भी इसी पहल का हिस्सा रहा। शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. उदय कुमार ने किया। इस अवसर पर सेक्टर-9 अस्पताल की विशेषज्ञ चिकित्सकों और अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रुचिका ताम्रकार ने बाल स्वास्थ्य, पोषण और नियमित टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीना गुहा ने महिलाओं में कैंसर जागरूकता, प्रजनन स्वास्थ्य, स्तनपान और मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सहायक प्रबंधक सुश्री लता मिश्रा ने स्वस्थ जीवनशैली एवं संतुलित



आहार के महत्व को बताया, जबकि सहायक प्रबंधक सुश्री शशि सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। नदिनी माइंस की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूजा शर्मा ने महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी दी। डॉ. साव्नी (डीएनबी) ने भी चिकित्सकीय परामर्श सत्र में योगदान दिया। शिविर में डीएवी और सीपीएस विद्यालयों की छात्राओं, शिक्षकों, संविदा महिला कर्मचारियों तथा

समस्याओं की पहचान, समय पर जांच और नियमित स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक किया गया। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा मरीजों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से नदिनी माइंस अस्पताल को कार्डियक मॉनिटर उपलब्ध कराया गया। इस पहल से अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सुश्री लता मिश्रा के संचालन में स्वास्थ्य विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। सही उत्तर देने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 20 पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन में

उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर अधिकारियों, अतिथियों और छात्राओं ने महिला स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देते हुए रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के महत्व को भी रेखांकित किया गया। इस आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. उदय कुमार, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. संबिता पंडा तथा महाप्रबंधक प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) श्री संजय कुमार का मार्गदर्शन रहा।

दीपावली से पहले बंद एवं खराब स्ट्रीट लाइटों के सुधार के लिए 15 लाख रुपये की सामग्री क्रय, पार्षद एवं महापौर निधि से भी कराए गए कार्य

दुर्ग/ नगर पालिक निगम। दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित 23 करोड़ से ज्यादा का बजट, फिर भी हजारों से अधिक स्ट्रीट लाइट बंद शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में नगर पालिक निगम, दुर्ग के विद्युत विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि निगम द्वारा विद्युत संधारण हेतु 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित नहीं है। निर्धारित बजट के अंतर्गत शहर की विद्युत व्यवस्था के सुचारु संचालन,खरखाव, सुचारु, विद्युत देयक एवं आवश्यक सामग्री क्रय सहित विभिन्न कार्य कराए जाते हैं। नगर निगम द्वारा शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों को बेहतर प्रकाश

सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्षद निधि एवं महापौर निधि के अंतर्गत भी स्ट्रीट लाइट क्रय करने की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त विधायक निधि से लगभग 40 लाख रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है। वहीं, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 50 लाख रुपये की लागत से ट्यूबलर रोपल क्रय कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने, नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्ट्रीट लाइटों के संधारण हेतु 15 लाख रुपये की लागत से आवश्यक सामग्री का क्रय भी किया गया है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना के तहत 68 इंटर्न की जॉइनिंग

160 इंटरनेशिप के लक्ष्य के तहत अब तक 109 इंटर्न ने ग्रहण किया कार्यक्रम

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास (एचआर-एलएंडडी) विभाग द्वारा प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना (पीएमआईएस) के तहत 68 इंटर्न की जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। संयंत्र में इस योजना के तहत कुल 160 इंटरनेशिप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब तक 109 इंटर्न कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।



गया। इसके पश्चात उन्हें तीन दिवसीय संयंत्र भ्रमण कराया गया। संयंत्र भ्रमण पूरा होने के बाद इंटर्न को संयंत्र के विभिन्न विभागों में पदस्थ किया जा रहा है। परिचयात्मक प्रशिक्षण के दौरान इंटर्न को संयंत्र के संगठनात्मक वातावरण, कार्यस्थल की अपेक्षाओं, व्यवसायिक आचरण एवं औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई।

वहीं, संयंत्र भ्रमण के माध्यम से उन्हें औद्योगिक परिचालन, उत्पादन प्रक्रियाओं तथा विभिन्न विभागों के कार्यों को करीब से समझने का अवसर मिला। इससे उन्हें अपने शैक्षणिक ज्ञान को व्यावहारिक कार्यों से जोड़ने में सहायता मिलेगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना का उद्देश्य युवाओं को वास्तविक

व्यावसायिक वातावरण में कार्य करने का अनुभव प्रदान करना तथा शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करना है। यह योजना युवाओं के कौशल विकास, कार्यस्थल के लिए तैयारी और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य करती है। बीएसपी का एचआर-एलएंडडी विभाग दस्तावेज सत्यापन, इंटरन के

पंजीयन एवं जॉइनिंग, परिचयात्मक प्रशिक्षण तथा संयंत्र भ्रमण के समन्वय के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पहल से युवाओं को औद्योगिक कार्यप्रणाली को समझने और भविष्य की व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।

महासमुंद। जिला मुख्यालय से 8 किमी दूर ग्राम लाफिनकला में 101 साल पुरानी रामलीला की परंपरा आज भी जीवंत है। बदलते दौर और मनोरंजन के आधुनिक साधनों के बीच गांव के युवा हर साल दशहरा पर रामलीला का मंचन कर सांस्कृतिक विरासत को सहेज रहे हैं। इस बार आयोजन बाल समाज के युवाओं ने किया, जिसमें बालिकाओं की भागीदारी विशेष आकर्षण रही।लीला मंडली के सचिव रामजी साहू ने बताया कि समय के साथ पात्र जुटाना कठिन हो गया है, फिर भी परंपरा को टूटने नहीं दिया जा रहा। पहले गांव में 3 से 9 दिनों तक रामलीला-कृष्णलीला के साथ श्रवण कुमार, राजा हरिश्चंद्र, मोरध्वज, चरणदास चोर, मयारू भोजी, सती नाग चंपा जैसे नाटकों का मंचन होता था। बुजुर्ग बताते हैं कि तब मनोरंजन के साधन कम थे, लोग रातभर लीला देखते थे और इससे धर्म, सत्य, त्याग व कर्तव्य की



शिक्षा मिलती थी। वहीं गांव शिक्षक गोवर्धन साहू व महेन्द्र पटेल ने कहा कि 101 वर्ष पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इससे धार्मिक संदेश के साथ सामाजिक चेतना भी फैलती है। इस वर्ष पुरुष पात्रों की कमी के कारण बालिकाओं को भी शामिल किया गया, जिन्होंने उत्साह से विभिन्न भूमिकाएं निभाकर आयोजन को सफल बनाया। यह गांव की बदलती सोच का भी प्रतीक बना। इस परंपरा की नींव स्व. सियाराम साहू, स्व. जीवन साहू, स्व.जगदेव साहू, स्व. उत्तम साहू, स्व. ओनुराम साहू,

लीलाराम साहू व सुखेन्द्र पटेल ने रखी थी। बाद में जगदीश साहू, सुकदेव साहू, अनूप राम साहू व मंगतू साहू ने इसे आगे बढ़ाया।इस वर्ष आयोजन में रामजी साहू, हरिराम साहू, गोवर्धन साहू, महेन्द्र पटेल, जनक राम साहू, संतराम साहू, पंचराम साहू,टीका पटेल, नेतन पटेल, भानू साहू, अनिल साहू, विजय साहू,पुराणिक साहू सहित अन्य युवाओं का विशेष सहयोग रहा। लाफिन कला की रामलीला अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में 42वें वार्षिक माइंस सेफ्टी फोर्टनाइट सेलिब्रेशन की फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के दलैराजहरा लौह अयस्क खदान द्वारा खदान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), बिलासपुर क्षेत्र-1 एवं 2 तथा रायगढ़ क्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 42वें वार्षिक खदान सुरक्षा पखवाड़ा समारोह 2026 (नॉन कोल माइंस) के अंतर्गत खदान सुरक्षा बोर्डी मीटिंग का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को भिलाई निवास के बहुउद्देशीय सभागार में किया गया।

समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता खदान सुरक्षा निदेशक, क्षेत्र-1 के अध्यक्ष श्री इरफन अंसारी, खदान सुरक्षा निदेशक एवं सह-अध्यक्ष, बिलासपुर क्षेत्र-2 श्री अलताफ हुसैन, उपाध्यक्ष खदान सुरक्षा एवं सह-अध्यक्ष, रायगढ़ क्षेत्र श्री सत्य कुमार पी., सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक (खदान) श्री कमल भास्कर, कार्यपालक निदेशक (रावघाट) श्री अरुण



दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने, मशीनों के सुरक्षित संचालन तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सभी संबंधित पक्षों की भूमिका पर विचार-विमर्श भी किया गया। 42वें वार्षिक खदान सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित जनरल बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए खदान सुरक्षा निदेशक एवं क्षेत्र-1 के अध्यक्ष श्री इरफन अंसारी ने

कहा कि खदान सुरक्षा पर किया गया निवेश सुरक्षित खनन एवं उत्पादन कार्यों की दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन, खदानों में नियमित निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षित कार्यप्रणाली, निरीक्षण दल के गठन में निर्धारित मानकों का ध्यान रखने तथा डिजिटल माध्यमों से सूचनाओं के प्रभावी संप्रेषण और निरीक्षण प्रक्रिया में

सभी संबंधित सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने खदान सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से प्राप्त निष्कर्षों और अनुभवों को संकलित कर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर बेहतर कार्ययोजना तैयार करने में सहायता मिलने के साथ ही जमीनी स्तर पर सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने तथा निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायक होगी। खदान सुरक्षा निदेशक एवं सह-अध्यक्ष श्री अलताफ हुसैन ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की खदानों की व्यापक सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए आयोजन को उच्च स्तर पर आयोजित करने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण, तकनीकी प्रतियोगिताओं एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से खदानों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ एवं नवाचारी

कार्यप्रणालियों को साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने स्मारिका में व्यावहारिक सुरक्षा उपायों, नवाचारों और उपयोगी लेखों को शामिल करने तथा सभी श्रेणियों की अधिकधिक खदानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन से विभिन्न खदानों के बीच उपयोगी कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान होगा और डीजीएमएस के शुन्य हानि एवं शुन्य दुर्घटना के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। कार्यपालक निदेशक (खदान) श्री कमल भास्कर ने 42वें वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह-2026 के अंतर्गत आयोजित प्रथम बैठक में सभी प्रतिभागियों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर क्षेत्र-1, बिलासपुर क्षेत्र-2 एवं रायगढ़ क्षेत्र की संयुक्त सहभागिता से आयोजित यह खान सुरक्षा सप्ताह व्यापक स्तर पर खान सुरक्षा के प्रति जागरूकता

बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आयोजन खदानों में सुरक्षित कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करने तथा सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करने में सहायक होगा। कार्यपालक निदेशक (रावघाट) श्री अरुण कुमार ने अपने उद्घोषण में बताया कि सेल की रावघाट परियोजना को 14 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली ग्रीनफ़ैल्ड खदान के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत 3 मिलियन टन की क्षमता के अनुरूप उत्पादन कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा इसके विकास में तेजी से प्रगति हुई है। उन्होंने कैप्टिव खदानों से लौह अयस्क का आपूर्ति के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि संशोधन के बाद कैप्टिव खदानों से उत्पादित लौह अयस्क की खुले बाजार में बिक्री भी की जा सकती है। इससे लौह अयस्क की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

संपादकीय

इस घटना की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला का ममता बनर्जी पर हमला करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह उनसे मिलना चाहती थी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में उनके आवास के पास एक महिला द्वारा हमले की कोशिश करने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

खड़े कर दिए हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता पर ही सरेआम हमले का प्रयास किया जाता है, तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगा! पार्टी के ममता समर्थक धड़े का आरोप है कि संबंधित महिला के हाथ में चाकू था।हालांकि इसकी सच्चाई गहन जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन सवाल है कि आरोपी महिला ममता के

ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेंध की कोशिश, उठे सवाल

सुरक्षा घेरे के इतने करीब कैसे पहुंच गई? इस बात की जांच-पड़ताल भी जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक हुई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य में पिछले लंबे समय से राजनीतिक हिंसा की खबरें भी आती रही हैं, लिहाज पुलिस को हर पछलू से इस घटना की छनबीन करनी चाहिए, ताकि सच सबके

सामने आ सके।खबरों के मुताबिक, ममता बनर्जी पर बीते मंगलवार को उस वक्त हमले की कोशिश की गई, जब वह दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने जा रही थीं। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों और वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपी महिला को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, इस घटना की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आरोपी

महिला का ममता बनर्जी पर हमला करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह उनसे मिलना चाहती थी। मगर यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या किसी प्रमुख नेता की सुरक्षा से जुड़े मामले को महज राजनीतिक आरोप मानकर उसकी गंभीरता को नजरअंदाज किया जा सकता है? कायदे से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर सुरक्षा में चूक का कोई

मामला बनता है, तो उसमें भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस घटना की संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन जब असहमति हिंसा की दहलीज तक पहुंच जाए, तो खतरा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता।

इसवर्ष बारिशमेंगिरावटकीवजहसेभावी संकटकोलेकर बढ़तीफिऊस्वाभाविक है।मगर फिलहालचिंता का कारण केवल बारिश नहीं, बल्कि जमीनपर उपलब्ध पानी को संभालनेकी हमारी घटती क्षमता है। देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर तेजी से नीचे जाना और दूसरी ओर उन्हीं जलाशयों की भंडारण क्षमता का गाद के कारण लगातार कम होते जाना आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है। सवाल यह नहीं है कि मानसून इस बार कितना अच्छा रहा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि मानसून से मिलने वाले पानी को हम कितना बचा पाए। गौरतलब है कि केंद्रीय जल आयोग 166 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी करता है। इन जलाशयों की कुल क्षमता 183.565 अरब घन मीटर है। मध्य-मई की स्थिति के अनुसार इनमें करीब 63 बीसीएम पानी ही बचा था । यानी लगभग 34.45 फीसद की स्थिति के अनुसार इनमें करीब 63 बीसीएम पानी ही बचा था। यानी लगभग 34.45 फीसद। इससे स्पष्ट है कि गर्मी के चरम दौर में देश के प्रमुख जलाशयों का लगभग दो-तिहाई भंडारण खाली हो चुका था। कई राज्यों में स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक रही और अनेक बांधों में पानी काफी कम हो गया।

(बलकार सिंह पुनियां) देश में 6,628 बड़े बांध हैं। इनमें से 1,681 बांध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 291 बांध सी वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। यानी देश के लगभग 26 फीसद बांध आधी सदी से अधिक पुराने है। इस वर्ष बारिश में गिरावट की वजह से भावी संकट को लेकर बढ़ती फिऊ स्वाभाविक है। मगर फिलहाल चिंता का कारण केवल बारिश नहीं, बल्कि जमीन पर उपलब्ध पानी को संभालने की हमारी घटती क्षमता है। देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर तेजी से नीचे जाना और दूसरी ओर उन्हीं जलाशयों की भंडारण क्षमता का गाद के कारण लगातार कम होते जाना आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है। सवाल यह नहीं है कि मानसून इस बार कितना अच्छा रहा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि मानसून से मिलने वाले पानी को हम कितना बचा पाए। गौरतलब है कि केंद्रीय जल आयोग 166 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी करता है। इन जलाशयों की कुल क्षमता 183.565 अरब घन मीटर है। मध्य-मई की स्थिति के अनुसार इनमें करीब 63 बीसीएम पानी ही बचा था। यानी लगभग 34.45 फीसद। इससे स्पष्ट है कि गर्मी के चरम दौर में देश के प्रमुख जलाशयों का लगभग दो-तिहाई भंडारण खाली हो चुका था। कई राज्यों में स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक रही और अनेक बांधों में पानी काफी कम हो गया।

यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलाशय केवल पानी जमा करने की जगह नहीं हैं। उनसे खेतों की सिंचाई होती है, शहरों और गांवों को पेयजल मिलता है तथा बिजली का उत्पादन भी होता है। जलाशयों में पानी कम होने का अर्थ है कि कृषि, पेयजल और ऊर्जा पर एक साथ दबाव बढ़ना। गर्मी के दिनों में पानी की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। अगर मानसून आने में देरी होती है या वर्षा सामान्य से कम या असमान रहती है, तो यह दबाव और अधिक बढ़ सकता है।

देश की जल समस्या का शायद सबसे गंभीर और अपेक्षाकृत कम चर्चित पहलू जलाशयों में लगातार बढ़ती गाद है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार भारत में जलाशयों में गाद जमाव संबंधी संकलन-2024 में 548 जलाशयों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया, जिनमें से 439 जलाशयों के आंकड़े विश्लेषण के लिए उपयुक्त पाए गए। एक अध्ययन के अनुसार, गाद जमने के कारण इन जलाशयों की सकल भंडारण क्षमता में औसतन 19.24 फीसद की कमी आ चुकी है। वहीं, जलाशयों की भंडारण क्षमता में प्रत्येक वर्ष औसतन 0.74 फीसद की कमी दर्ज की जा रही है।

यह आंकड़ा भविष्य की भयावह तस्वीर समझने के लिए पर्याप्त है। अगर जलाशय में पानी पहुंचाने वाली नदियां और बरसाती धाराएं

अपने साथ मिट्टी एवं तलछट लाती रहें तथा जलाशयों में गाद जमा होती रहे, तो कुछ वर्षों बाद अच्छी बारिश होने पर भी हमारे पास पानी रखने की पर्याप्त क्षमता नहीं होगी। यानी एक तरफ वर्षा की अनिश्चितता और दूसरी तरफ घटती भंडारण क्षमता। यह दोहरी चुनौती है।

ऊपर की मिट्टी को बहने से नहीं रोका गया, तो नीचे जलाशयों से गाद निकालने का काम लगातार चलता रहेगा और समस्या कभी खत्म नहीं होगी। कृषि क्षेत्र में भी दृष्टिकोण बदलना होगा। भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोग कृषि में होता है। ऐसे में कम पानी में अधिक उत्पादन की



यह समस्या पुराने जलाशयों में अधिक गंभीर हो सकती है। नेशनल रजिस्टर ऑफ स्पेसिफाइड डैम्स-2025 के अनुसार देश में 6,628 बड़े बांध हैं। इनमें से 1,681 बांध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 291 बांध सी वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। यानी देश के लगभग 26 फीसद बांध आधी सदी से अधिक पुराने हैं। उम्र अपने आप में किसी बांध को असुरक्षित नहीं बनाती, लेकिन समय बीतने के साथ संरचनात्मक रखरखाव, जलाशय की क्षमता, गाद और जलग्रहण क्षेत्र में बदलाव की नियमित समीक्षा जरूरी है।

गाद की समस्या का समाधान केवल जलाशय से गाद निकालने तक सीमित नहीं हो सकता। दरअसल, गाद का बड़ा स्रोत जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी का कटाव है। इसलिए जलइयों और नदी घाटियों में वनों की कटाई, भूमि क्षरण, अवैज्ञानिक खेती, निर्माण गतिविधियों और जलग्रहण क्षेत्रों के कमजोर प्रबंधन को रोकना भी उतना ही आवश्यक है। अगर

दिशा में फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, 'ड्रिप' और 'स्प्रिंकलर' जैसी तकनीकों का विस्तार जरूरी है। जिस क्षेत्र में पानी सीमित है, वहां अत्यधिक जल मांग वाली फसलों को बढ़ावा जल संकट को बढ़ाएगा। वर्ष 2025 के दौरान देश में बांधों का मानसून पूर्व और उसके बाद निरीक्षण किया गया। इसमें तीन बांधों को सबसे गंभीर श्रेणी-एक तथा 216 बांधों को श्रेणी-दो में रखा गया। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि बांधों की सुरक्षा को केवल उनके निर्माण के समय ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी समयावधि के दौरान प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। नियमित निरीक्षण, समयबद्ध रखरखाव और आवश्यकता अनुसार पुनर्वास से ही बांधों की सुरक्षा और उनकी उपयोगिता लंबे समय तक सुनिश्चित की जा सकती है। भारत ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना जैसे कदमों से इस दिशा में संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। अब

जरूरत इस बात की है कि इन व्यवस्थाओं का प्रभाव राज्यों और स्थानीय स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रत्येक बड़े बांध के लिए नियमित निरीक्षण, समयबद्ध रखरखाव, आपातकालीन कार्ययोजना, जलाशय की वास्तविक भंडारण क्षमता का आकलन तथा गाद प्रबंधन को अनिवार्य रूप से जल प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

दरअसल, जल संकट का स्थायी समाधान केवल अच्छी बारिश नहीं है। मानसून अच्छा हो, तो भी यदि हम पानी को रोक नहीं पाए और जलाशयों की क्षमता घटती रही तथा भूजल का अत्यधिक दोहन जारी रहा, तो अगले कुछ वर्षों में समस्या गंभीर रूप से हमारे सामने खड़ी होगी। दूसरी ओर, अगर मानसून कमजोर रहा, तो मौजूदा जल भंडारण की सीमाएं और स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए मानसून का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन जल प्रबंधन को मानसून से अलग एक निरंतर राष्ट्रीय अभियान बनाना होगा। जलाशयों की निगरानी केवल जलस्तर मापने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वास्तविक भंडारण क्षमता, गाद की मात्रा, जलग्रहण क्षेत्र और भविष्य की जल मांग का भी नियमित आकलन होना चाहिए।

इस समस्या पर सबसे बड़ी जरूरत सोच बदलने की है। पानी को असीमित प्राकृतिक संसाधन मानने के बजाय सीमित और मूल्यवान संपदा समझना होगा। जिस पानी को आज हम व्यर्थ बहने देते हैं, वही कल खेत, गांव, शहर और उद्योग के लिए जीवनरेखा बन सकता है।

देश के पास बांधों का विशाल नेटवर्क है। इसके संग्रहण क्षमता 253.95 अरब घन मीटर है। यह क्षमता हमारी बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी उपयोगिता तभी कायम रहेगी, जब हम जलाशयों की उम्र, गाद और घटती क्षमता को गंभीरता से लें। आज जरूरत नए जलाशय गिनने से अधिक मौजूदा जलाशयों की बची हुई क्षमता बचाने की है।

जल सुरक्षा केवल बारिश से नहीं आएगी। इसके लिए जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण, गाद नियंत्रण, पुराने बांधों का पुनर्वास, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को एक साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना होगा। आखिरकार सवाल यह नहीं है कि आसमान से कितना पानी बरसेगा। सवाल यह है कि धरती पर गिरने वाली हर बूंद में से हम कितनी बूंदें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज पाएंगे।

फीबीज कल्चर या सामाजिक सुरक्षा ? जानिए भारत के विकास और चुनावी वादों की असल चुनौती

(सुधीर कुमार) भारत में असली चुनौती लोक कल्याण और राजकोपीय विवेक में संतुलन की है। मुफ्त चुनावी वादों के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार में दीर्घकालिक निवेश ही वास्तविक नागरिक सशक्तीकरण और टिकाऊ विकास है।

देश के विकास में एक बड़ी चुनौती लोक कल्याण और राजकोपीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की है। एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं हैं, तो दूसरी ओर चुनावों में तत्काल लाभ वाले वादे भी सामने आते हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी है कि लोक कल्याण कहां तक सामाजिक अधिकार है और किस बिंदु पर वह राजकोपीय विवेक की परीक्षा बन जाता है। भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की दिशा स्पष्ट करता है।

प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प रखती है। साथ ही ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसमें लोक कल्याण बढ़े और आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता न रहे। इसके अलावा आजीविका, संसाधनों के व्यापक हित में वितरण और आर्थिक व्यवस्था में धन के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकने जैसे उद्देश्यों का उल्लेख भी किया गया है।

ये प्रावधान न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं और संविधान इन्हें शासन में मूलभूत मानता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा को महज राजनीतिक दान समझना संविधान की कल्याणकारी दृष्टि को संकुचित करने जैसा होगा। इसी संदर्भ में जीवन के अधिकार को भी केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं माना गया है। संविधान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण फैसले में गरिमापूर्ण जीवन को भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जोड़ा था। ऐसे में गरीब नागरिकों को न्यूनतम गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने वाली सार्वजनिक व्यवस्था को सामान्य चुनौती 'मुफ्त सौगात' मानना उचित नहीं होगा। यहाँ से सामाजिक सुरक्षा और मुफ्त सौगात के बीच जरूरी भेद उभरता है। अच्छी सामाजिक नीति वह है, जो व्यक्ति को क्षमता बढ़ाती है, जोहिसम कम करती है और उसे भविष्य में अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेयजल, रोजगार गारंटी और गरीबों के लिए लक्षित

सहायता सार्वजनिक निवेश है। इनका लाभ पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को मिलता है। इसके विपरीत ऐसी योजनाओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है, जिनमें लाभ का संबंध किसी स्पष्ट सामाजिक लक्ष्य, आवश्यकता या दीर्घकालिक क्षमता निर्माण से नहीं है। मगर किसी वस्तु या सेवा का मुफ्त होना अपने आप में उसे लोकलुभावन या अनुपादक नहीं बना देता।

मुफ्त बिजली की सीमित सहायता, छत्र को डिजिटल उपकरण, किसान को सिंचाई सहायता या महिला को परिवहन में रियायत के प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं। उनका मूल्यांकन पात्रता, लागत और परिणामों के आधार पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि खर्च का उद्देश्य क्या है और उससे सार्वजनिक हित कितना हासिल होता है।

चुनावी घोषणापत्रों को लेकर कानून और न्यायापालिका का रुख भी यही जटिलता दिखाता है। वर्ष 2013 में एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनावी घोषणापत्र के वादों को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। साथ ही अदालत ने निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों से परामर्श कर घोषणापत्रों के लिए दिशा-निर्देश बनाने को कहा था।

निर्वाचन आयोग के वर्तमान दिशा-निर्देश कल्याणकारी योजनाओं के वादों पर आपत्ति नहीं करते, लेकिन राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं कि वे ऐसे वादों से बचें, जो चुनाव प्रक्रिया की शुचित्ता या मतदाताओं के स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करें। मुफ्त सौगातों को लेकर वर्ष 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठी बहस ने इस प्रश्न को फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। मुद्दा केवल यह नहीं था कि कोई योजना मुफ्त है या नहीं, बल्कि यह था कि ऐसी घोषणाओं के वित्तीय प्रभाव, राजकोपीय स्थिरता और चुनावी समानता का आकलन कैसे हो। जोहिसम तब है, जब ऐसी प्रतिक्रियाएं जताई जाएं, जिनके स्थायी राजस्व स्रोत न हों और जिनका भार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे या रोजगार सृजन पर पड़े। हर सबसिडी को आर्थिक अपव्यय कहना भी उचित नहीं। कृषि, खाद्य, ऊर्जा या परिवहन में लक्षित सहायता सामाजिक स्थिरता और आर्थिक अवसरों का साधन बन सकती है। इसलिए सवाल 'सबसिडी बनाम विकास' का नहीं, बल्कि बेहतर प्राथमिकताओं, लक्षित लाभ और टिकाऊ वित्त का है। दुनिया के कुछ अनुभव इस बहस को उपयोगी संदर्भ देते हैं। ब्राजील का बोल्सा फमीलिया दकद सहायता को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों से जोड़ने वाला प्रमुख उदाहरण रहा है।

भारत के पास वैज्ञानिक प्रतिभाएं भरपूर, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहीं बड़ी खोज?

वैज्ञानिक प्रतिभाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भारत को नोबेल पुरस्कार ना के बराबर क्यों मिलते हैं? लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि दुनिया में बड़े वैज्ञानिक बदलाव लाने वाले देश ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? और हमारे वैज्ञानिकों के रास्ते में कौन-सी बाधाएं हैं?इसका जवाब सिर्फ पैसा नहीं है, हालांकि पैसे की अहमियत जरूर है। अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 3.4 फीसदी हिस्सा शोध और विकास पर खर्च करता है। जर्मनी 3 फीसदी से ज्यादा, जापान 3.5 फीसदी से अधिक और दक्षिण कोरिया 5 फीसदी से ज्यादा खर्च करता है।

(कामिनी वालिया)

चीन का उदाहरण अहम है। शोध और विकास पर उसका निवेश बढ़ा है और इसके साथ ही वह दुनिया में सस्ती तकनीक का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होते ही भारत में एक सवाल फिर उठने लगता है। वैज्ञानिक प्रतिभाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भारत को नोबेल पुरस्कार ना के बराबर क्यों मिलते हैं? लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि दुनिया में बड़े वैज्ञानिक बदलाव लाने वाले देश ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? और हमारे वैज्ञानिकों के रास्ते में कौन-सी बाधाएं हैं?इसका जवाब सिर्फ पैसा नहीं है, हालांकि पैसे की अहमियत जरूर है। अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 3.4 फीसदी हिस्सा शोध और विकास पर खर्च करता है। जर्मनी 3 फीसदी से ज्यादा, जापान 3.5 फीसदी से अधिक और दक्षिण कोरिया 5 फीसदी से ज्यादा खर्च करता है। चीन भी इस मद में जीडीपी का करीब 2.7 फीसदी खर्च करने के करीब पहुंच रहा है। इसके मुकाबले भारत में शोध और विकास पर कुल खर्च जीडीपी का महज 0.64 फीसदी है।

लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि शोध के लिए पैसा कौन देता है। भारत में शोध और विकास पर होने वाले कुल खर्च का करीब 40 फीसदी हिस्सा उद्योग जगत से आता है। अमेरिका और चीन में यह हिस्सेदारी करीब तीन-चौथाई है। यानी भारत में शोध का दायर भी छोटा है और

इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी कम है।

इसके साथ ही वैज्ञानिकों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वे नई तकनीकें विकसित करें, उत्पाद बनाएं, शोध को कारोबार में बदलें और समस्याओं का समाधान निकालें। देश की जरूरतों के लिहाज से ये लक्ष्य जरूरी हैं, लेकिन तकनीक कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे मांग



के मुताबिक तुरंत तैयार कर दिया जाए। हम शोध के आखिरी चरणों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि शुरुआत में होने वाले बुनियादी शोध में जरूरत के मुताबिक निवेश नहीं कर रहे हैं।

बुनियादी विज्ञान पर ध्यान देने की जरूरत: मिसाल के तौर पर, बीमारी की

जांच करने वाला कोई उपकरण विकसित करने से पहले कई साल तक उस बीमारी की प्रकृति, रोगाणु के व्यवहार, शरीर की प्रतिक्रिया, जैविक संकेतकों और अन्य प्रक्रियाओं पर काम करना पड़ सकता है। तभी जाकर कोई उत्पाद तैयार करना संभव होता है। बुनियादी विज्ञान वह आधार है, जहां से नए विचार और आविष्कार जन्म

लेते हैं। भारत को अपनी शोध व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत यहीं से करनी होगी। सबसे पहले, सरकार और शोध से जुड़ी एजेंसियों को बुनियादी विज्ञान के लिए अलग से धन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा के आधार पर मिलने वाली शोध राशि का एक तय हिस्सा ऐसे शोध के लिए

रखा जाना चाहिए, जिनके सवाल वैज्ञानिक खुद चुनें और जिनका मकसद अपनी जिज्ञासा के आधार पर नई खोज करना हो। ऐसे हर शोध से पेटेंट, उत्पाद या तकनीक तैयार करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

दूसरा, शोध के लिए मिलने वाली राशि को तीन स्पष्ट हिस्सों में बांटना चाहिए—नई खोज, खोज को उपयोगी तकनीक में बदलना और उसका व्यावहारिक इस्तेमाल। इन तीनों के लिए अलग-अलग समय-सीमा और सफलता के मानक तय होने चाहिए।

तीसरा, भारत को ऐसे शोध के लिए लंबे समय तक आर्थिक मदद देनी चाहिए। वैज्ञानिक काम की सख्त समीक्षा जरूर हो, लेकिन प्रशासनिक दखल और छोटी-छोटी बातों पर निगरानी कम होनी चाहिए।

चौथा, देश में शोध की साझा सुविधाओं का राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना जरूरी है। जैनीम, प्रोटीन, उन्नत इमेजिंग, जैविक नमूनों के भंडार, संरचनात्मक जीवविज्ञान, एआई और कंप्यूटिंग जैसी सुविधाएं अलग-अलग संस्थानों के वैज्ञानिकों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके अलावा, हमें शोध को देखने और वैज्ञानिकों के काम का आकलन करने का तरीका भी बदलना होगा। शोध पत्रों की संख्या, पत्रिकाओं का प्रभाव, पेटेंट और शोध के लिए मिली राशि का कितना इस्तेमाल हुआ, इन सबके आंकड़े जुटाना आसान है। लेकिन इनसे यह पता नहीं चलता कि वैज्ञानिक ने कोई महत्वपूर्ण नई खोज की है या नहीं। वैज्ञानिकों के काम का आकलन करते समय उनकी मौलिकता,

शोध के नतीजों को दोबारा हासिल कर पाने की क्षमता, उनके उठाए सवालों की अहमियत और नए ज्ञान के निर्माण को महत्व देना चाहिए।

इसके साथ ही उपयोगी आंकड़े, शोध मंच और तकनीक विकसित करने के काम तथा विज्ञान या स्वास्थ्य नीति पर शोध के असर को भी मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए शोध की पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से तैयार करना होगा।

चीन से सबक: चीन का उदाहरण इस मामले में अहम सबक देता है। शोध और विकास पर उसका निवेश बढ़ा है और इसके साथ ही वह दुनिया में सस्ती तकनीक का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। 2024 में दुनिया के करीब 80 फीसदी सौर ऊर्जा पैनल माइड्रूल और बैटरी सेल चीन में बने। वहीं, 2025 में दुनिया में बनने वाली इलेक्ट्रिक कारों में चीन की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी तक पहुंच गई। इससे यह सबक मिलता है कि नई खोजों को इंजीनियरिंग, विनिर्माण और बाजार से जोड़ना कितना जरूरी है। भारत के पास एक बड़ी प्राकृतिक ताकत है। यहां की विशाल और विविध आबादी वैज्ञानिक शोध के लिए व्यापक अवसर देती है। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो युवा वैज्ञानिकों को किसी नए और लौकिक हटकर सवाल पर 10 या 15 साल तक काम करने का मौका दे। वे असफल हों, अपनी दिशा बदलें और फिर से कोशिश करें, लेकिन तुरंत कोई उत्पाद तैयार न कर पाने के लिए उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

न्यूज ब्रीफ

म्यूल अकाउंट से करोड़ों मे लेन-देन, आरोपी को 3 साल की सजा



मुंगेली. साइबर अपराध के जरिए ठगी गई करोड़ों रुपये की रकम को बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त करने और उसके लेन-देन में शामिल का इस्तेमाल करने के मामले में मुंगेली न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के अपराध क्रमांक 77/2025 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में आरोपी संजीव खांडे को दोषी ठहराते हुए 10 नवंबर के अर्थदंड से दंडित कर दिया गया है. सत्र न्यायाधीश मुंगेली गिरिजा देवी मेरावी ने यह निर्णय सुनाया. प्रकरण के अनुसार, आरोपी झा संजीव खांडे, उम्र 38 वर्ष, पिता

एकतरफा तलाक रद, अब पति-पत्नी दोनों को मिलेगा अपनी बात रखने का मौका



बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर निवासी योगेश अग्रवाल और उनकी पत्नी शीतल अग्रवाल के बीच एकतरफा तलाक के डिक्री को लेकर चल रहे विवाद में परिवार न्यायालय को दोनों पक्षों के साथ दर्ज करने के बाद फैसला करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने पत्नी की अर्जी पर साक्ष्य लेने से इन्कार करने संबंधी परिवार न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया। योगेश अग्रवाल ने परिवार न्यायालय, रायपुर में तलाक की याचिका दायर की थी।उनके पक्ष में एकतरफा तलाक की डिक्री पारित हुई। इसके बाद शीतल अग्रवाल ने आवेदन देकर डिक्री निरस्त करने की मांग की। पति ने 17 जुलाई

पांच लाख मुनाफे का लालच देकर 1.67 लाख की ठगी

पेण्ड्रा. जिले के पेण्ड्रा में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला को एक लाख रुपये के बदले पांच लाख रुपये का मुनाफा देने का लालच देकर कथित तौर पर 1 लाख 67 हजार रुपये की ठगी की गई. वर्ष 2022 में हुई इस घटना को लेकर महिला ने पहले दिल्ली के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी. अब सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में कारवाई के निर्देश दिए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेण्ड्रा की पुरानी बस्ती निवासी 42 वर्षीय ज्योति गुप्ता पति दीपचंद गुप्ता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में मोबाइल के माध्यम से एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था. उसने एक लाख रुपये जमा करने पर पांच लाख रुपये का फायदा होने का लालच दिया. उसकी बातों में आकर महिला ने अलग-अलग किश्तों में यूपीआई के माध्यम से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंदौर शाखा के एक खाते में कुल 1

घरघोड़ा में 1 नवंबर से पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच पर प्रतिबंध

रायगढ़. नगर पंचायत घरघोड़ा ने प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने और नगर में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच के उपयोग, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2026 से लागू होगा. इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंधित सामग्री जप्त करने के साथ जुर्माने की कारवाई की जाएगी. नगर पंचायत परिषद की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. परिषद के अनुसार, पॉलीथिन और प्लास्टिक कचरे के कारण सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलती है. इन समस्याओं को



देखते हुए प्रतिबंध लागू करने की तैयारी की गई है. नगर पंचायत ने शोक व्यापारियों, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं को नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण, परिवहन और आपूर्ति नहीं करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही दुकानदारों, व्यापारियों, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, भोजनशास्त्र संचालकों और साप्ताहिक हाट-बाजार के विक्रेताओं से 1 नवंबर से पहले मौजूदा स्टॉक खत्म करने अथवा वापस करने का अपील की गई है.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने 14.25 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

मुंगेली और बिलासपुर में बनेंगे नए पुल

बिलासपुर. सड़क संपर्क और आवागमन की सुविधाओं को मजबूत करने लोक निर्माण विभाग ने मुंगेली और बिलासपुर जिलों में दो नए पुलों के लिए राशि मंजूर की है। दोनों पुलों और उनके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए कुल 14 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने दोनों कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। मुंगेली जिले के



तखतपुर-बरेला मार्ग पर मनियारी नदी में मौजूदा जलमग्निय पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल तथा बिलासपुर जिले के बेलगढ़ना-कोंचरा-खोंगसरा मार्ग पर डोंगानाला में उच्च स्तरीय पुल के

निर्माण शामिल हैं। दोनों पुलों के साथ पहुंच मार्ग भी बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने तखतपुर-बरेला राज्य मार्ग में मनियारी नदी पर जलमग्निय पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान में वहां जलमग्निय पुल होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने पर

स्थान पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपए मंजूर किए हैं। वर्तमान में वहां जलमग्निय पुल होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने पर

दीपावली से पहले प्रदूषण पर उठे सवाल रायगढ़ में शिव शक्ति स्टील प्लांट के धुएं से ग्रामीण परेशान

रायगढ़. दीपावली के पहले औद्योगिक प्रदूषण को लेकर रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने शिव शक्ति स्टील प्लांट से निकलने वाले धुएं और धूल से आसपास के वातावरण पर असर पड़ने की शिकायत की है। उनका आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला काला धुआं और उड़ती धूल लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर उड़ने वाली बारीक धूल से दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होती है। धूल आंखों में जाने और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। उनका कहना है कि सड़क पर धूल का गुबार होने से वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना का आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण के साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि



प्लांट के आसपास पेड़-पौधों की पत्तियों पर काली धूल जम रही है। इससे क्षेत्र की हरियाली और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। किसानों को भी फसलों पर औद्योगिक धूल जामने से संभावित नुकसान की चिंता है। हालांकि, प्रदूषण के वास्तविक स्तर और फसलों पर इसके प्रभाव की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर संबंधित विभागों और जिला प्रशासन तक शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन उन्हें स्थायी राहत नहीं मिली है। उन्होंने पर्यावरण विभाग और प्रशासन से प्लांट के उत्सर्जन, धूल की स्थिति और आसपास की

वायु गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि जांच में पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति और चिमनियों से निकलने वाले उत्सर्जन की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागों की जांच या कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रदूषण के स्तर, उसके प्रभाव और शिकायतों पर हुई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रशासन तथा पर्यावरण विभाग की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

धान खरीदी से पहले प्रशासन सख्त, 7 चेक पोस्ट पर होगी निगरानी

बिलासपुर. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले बिलासपुर जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने वालों पर नजर रखने की तैयारी की है. जिले के 7 चेक पोस्ट पर निगरानी की जाएगी. इनमें वन विभाग के 6 और खनिज विभाग का 1 चेक पोस्ट शामिल है, जहां अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अवैध धान के परिवहन और खपाने पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं.

अवैध संबंध के शक में युवक पर चाकू से हमला

बिलासपुर. सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मुडुपार में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान रमाशंकर सिंदार (45 वर्ष), निवासी मुडुपार मौहारापारा, थाना सीपत के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी और रितिक कश्यप उर्फ करन के बीच अवैध संबंध है. इसी संदेह के चलते वह रितिक से दुश्मनी रखता था. पुलिस ने आरोपी चाकू बरामद कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. टीआई राजेश मिश्रा ने बताया कि घटना 1 सितंबर की रात करीब 8 बजे की है. ग्राम मुडुपार

भाटापारा निवासी समीर कुर्मी (19 वर्ष) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रमाशंकर सिंदार ने उसके भाई रितिक कश्यप पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया. आरोपी ने रितिक के पेट, सीने और बाएं हाथ की कोहनी के पास चोट पहुंचाई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की. घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कोरबा के घंटाघर क्षेत्र में मौजूद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम कोरबा खाना हुई.

ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास सड़क पर मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश

रायगढ़. शहर के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क पर शव मिलने की सूचना मिलते ही जुटमिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के शरीर पर सीने में चोट के निशान बताए जा रहे हैं, जिसके बाद घटना की संदिग्ध परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास सड़क पर व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक की पहचान करने के प्रयास शुरू किए।

जिले का इकलौता रेलवे आरक्षण केंद्र पर लगा ताला बड़े नेता, बड़े वादेय फिर भी जनता में मायूसी

मुंगेली. मुंगेली जिले के साथ रेलवे की बेरुखी का आलम यह है कि जिले में आज तक रेल लाइन नहीं पहुंची और अब टिकट बुकिंग की उपलब्ध सुविधा भी बंद पड़ी है। शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित जिले का एकमात्र रेलवे आरक्षण केंद्र पिछले कुछ सप्ताह से बंद होने के कारण यात्रियों को टिकट नबनवाने के लिए करीब 50 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाना पड़ रहा है। जो बिलासपुर नहीं जा सकते उन्हें स्थानीय एजेंटों के घरोंसे बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस



सबके बीच अहम सवाल यह है कि बीते कई सालों से मुंगेली वासियों को रेलवे की सीमात मिलने की चर्चाएं गर्म होती हैं जिसके उपरान्त कभी स्वागत का दौर तो कही आभार प्रदर्शन का दौर नजर आने लगता है। किंतु बीते कुछ सप्ताह से नगर में

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, खरसिया कांग्रेस का प्रदर्शन

रायगढ़. चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर गुन्चरा को खरसिया में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक उमेश पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदनपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय से तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एसडीएम खरसिया को ज्ञापन सौंपकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की।

शासकीय सेवाओं तक पहुंच हुई सुगम डिजिटल सुविधा से एक ही माध्यम पर मिले जरूरी दस्तावेज



अन्य जरूरी कार्यों में पड़ती है। ऐसे में सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन एवं प्रमाण पत्र संबंधी सुविधा मिलने से नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में

मदद मिलती है। मानसी ने सेवा सेतु के संचालन के लिए शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसी सुविधाएं नागरिकों के लिए उपयोगी हैं।

धान खरीदी से पहले प्रशासन सख्त, 7 चेक पोस्ट पर होगी निगरानी

बिलासपुर. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले बिलासपुर जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने वालों पर नजर रखने की तैयारी की है. जिले के 7 चेक पोस्ट पर निगरानी की जाएगी. इनमें वन

विभाग के 6 और खनिज विभाग का 1 चेक पोस्ट शामिल है, जहां अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अवैध धान के परिवहन और खपाने पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं.

आज से शुरू होगी बिजली बंदी

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बिजली कंपनी ने निर्माण और रखरखाव कार्य के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली बंद रखने की सूचना जारी की है. आज से 28 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. शनिवार को 33/11 केवी यूनिवर्सिटी उपकेंद्र से जुड़े 11 केवी बिरकोना फीडर, कोनी, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कालेज फीडर बंद रहेंगे. इससे बड़ी कोनी, पेटेल पंप, गणेश इन्क्लेव, कंचन विहार, छोटी कोनी, और गुरु धासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्र प्रभावित होगा.

संचालित एक मात्र टिकट केन्द्र पर लटकने वाले ताक़े ने ऐसे कई सवाल छोड़ दिये हैक्या मुंगेली की जनता को हर छोटी जरूरत के लिए दूसरे शहरों के चकर काटने के लिए छोड़ दिया गया है? रेल लाइन नहीं, आरक्षण केंद्र भी बंद-जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 में मुंगेली के पुराना बस स्टैंड में रेलवे टिकट आरक्षण केन्द्र शुरू किया गया था। वह जिले का एकमात्र केंद्र था, जिससे मुंगेली और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती थी।

रायगढ़ अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर महेंद्र यादव समेत तीन प्रत्याशी मैदान में

रायगढ़. जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के द्विवार्षिक चुनाव 2026-28 को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। 23 अक्टूबर तक जमा नामांकन के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र सिंह यादव, मनोज कुमार तिवारी और शतेंद्र कुमार सिंह ने दावेदारी पेश की है। सचिव पद के लिए पांच प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। संघ के अन्य पदों के लिए भी अधिवक्ताओं ने नामांकन जमा किए हैं। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 4 नवंबर 2026 को होगा और मतगणना 5 नवंबर को निर्धारित की गई है। विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय में सरगमियां बढ़ गई हैं।अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र सिंह यादव, मनोज कुमार तिवारी और शतेंद्र कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। उपाध्यक्ष पद के लिए प्रवीर क्रांति राय और संजय कुमार शर्मा प्रत्याशी हैं।

विशेष आमंत्रण पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य

नक्सल मुक्त उत्सव

2026

नक्सल मुक्त
छत्तीसगढ़
सुरक्षित छत्तीसगढ़
समुद्ध छत्तीसगढ़

सम्मान समारोह

सेना के शूरवीरों एवं कर्मयोगियों का
• सम्मान समारोह •

दिनांक :

25.10.2026



समय :

11:00 AM



स्थान :

C. A. भवन

Civic Center, भिलाई

आयोजक

LP NEWS

लोकतंत्र प्रहरी प्रोडक्शन एंड मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड

एवं



एस. आर. हॉस्पिटल एण्ड कॉलेज

चिखली, दुर्ग (छ.ग.)

